भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

 **राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2438**

**बुधवार, 08 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**महंगाई को रोकने के उपाय**

**अता.प्र.सं. 2438. श्री रिपुन बोराः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि मई, 2018 का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) गत आठ महीनों के दौरान सर्वाधिक महंगाई दर को दर्शाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सब्जियों की कीमतों ने 12 महीनों की औसत महंगाई दर के 65 प्रतिशत को पार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मई में ईंधन और बिजली की कीमतों में भी लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो गत दो वर्षों की तुलना में लगातार अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के पास महंगाई और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रस्ताव हैं?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर. चौधरी)**

**(क):** मई, 2018 के लिए डब्‍ल्‍यूपीआई (2011-12) पर आधारित मुद्रास्‍फीति दर अनंतिम रूप से 4.4 प्रतिशत थी जो कि पिछले 8 माह के दौरान उच्‍च दर है।

**(ख):** जी, नहीं।

**(ग):** मई, 2018 के लिए डब्‍ल्‍यूपीआई 2011-12 पर आधारित ईंधन और विद्युत के लिए मुद्रास्‍फीति की अनंतिम दर 11.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था, जो कि जून, 2017 के बाद उच्‍च दर है।

**(घ):** सरकार द्वारा जरूरी खाद्य वस्‍तुओं के मूल्‍यों को स्थिर रखने हेतु समय-समय पर विभिन्‍न उपाय किए हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ आयात एवं निर्यात शुल्‍क, न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य, निर्यात प्रतिबंध आदि जैसे व्‍यापार एवं वित्‍तीय नीति साधनों का उचित समुपयोजन शामिल है। घरेलू उपलब्‍धता को नियमित तथा मूल्‍यों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार उत्‍पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्‍साहित करने के लिए उच्‍च न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों का प्रावधान करती है और भंडारण सीमाएं लागू करती है। इसके अलावा, सरकार द्वारा कृषि संबंधी वस्‍तुओं के मूल्‍यों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता के लिए मूल्‍य स्थिरता निधि योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*